



बुधवार, 18 सितंबर 2024, लखनऊ



sattasanket@gmail.com

R.N.I. No.: UPHIN/2016/69492

वर्ष 09, अंक 106 04 पेज, मूल्य ₹1.00



मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से उनके सरकारी आवास पर आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर के शिष्याचार भेंट की।

खास खबर

नहीं चलेगा बुलडोजर!

देशभर में बुलडोजर कार्टवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, कहा- हमारी अनुमति से ही लें एकशन

नई दिल्ली, एजेंसी।

पुलिस अपाराधियों को नहीं

छोड़ेंगी: राजभर

सुलभानपुर। जिले के प्रधानी मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिल देशभारा पुलिस के ऊपर कोई फायरिंग दोषाग्नि तो वह माला-फूल नहीं बरसाएगी। उसका आधार कांड नहीं मार्गीगी, कि देखे किस जाति के हो। पुलिस अपने बचाव के लिए गोली चलाएगी मांगलवार को सुभासपा अध्यक्ष और मंत्री जयपर मुलानपुर रोड पर थे। सरापा डैक्टी कांड में पांच संस्तंबर को ढेर राजभर सुलभानपुर एनकाउंटर पर मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब दे रहे थे। कहा, महापुरो के शेलेश राजभर को लगी गोली पर अखिलेश और राहुल वर्मों चर्चा नहीं करते।

केजरीवाल का इस्तीफा

चुनावी चाल: मायावती

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सुप्रीमो मायावती ने मंगलवार को कहा कि आम आदित्य पार्टी (आप) संघोंक अर्वाची जीवनी का इस्तीफा नहीं देना चाहिए वे जीवनी नहीं रखती है। उन्होंने कहा कि श्री केजरीवाल के लिए समय तक जेल में रहने के कारण दिल्ली की जनता समझती है कि वे अपनी जीवनी नहीं रखते हैं। उन्होंने बुलडोजर के इस्तेमाल पर यह आपसी परित्यक्त है और कहा कि उन्होंने बुलडोजर के लिए एक बार भी आपसी परित्यक्त है। उन्होंने कहा कि श्री केजरीवाल के लिए समय तक जेल में रहने के कारण दिल्ली की जनता समझती है कि वे अपनी जीवनी नहीं रखते हैं। इनकी चुनावी चाल व राजनीतिक घैरवर्गों, किन्तु उनके लिए समय तक जेल में रहने के कारण दिल्ली की जनता ने जेल में रहने के कारण घैरवर्गों व समझाएँ छोड़ी हैं। उसका काव्य। उनका हिसाब कौन देगा उन्होंने कहा सत्ता व विपक्ष के बीच राजनीतिक लड़ाई शरुआत तक उन्हें देश व जनता वाली है।

मोदी करेंगे हरियाणा

में तीन रैलियां

चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोनीपत, हिंसर और पलवल में रैलियां करेंगी। हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मोहन बड़ौली ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री 26 सितंबर को सोनीपत में और हिंसर तथा पलवल में दो अक्टूबर को रैली करेंगे। उन्होंने बताया कि इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राजा मंत्री राजीव गोपनीय एवं समरेश गांधी नेता जयपाल प्रत्याशियों के प्रचार के लिए आयोगी श्री बड़ौली ने बताया कि पार्टी का चुनावी घोषणाकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जयपाल नहीं बुलडोजर को रोकत में जारी करेंगे।

भारत के अमृतकाल के सारथी हैं पीएम मोदी: सीएम योगी



योगी ने किये बाबा विश्वनाथ के दर्शन, प्रसाद में बांटा 74 किलो का लड्डू।

मुख्यमंत्री ने विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एमएसएमई इकाइयों को वितरित किया 50,000 करोड़ का ऋण

आम लोग सुरक्षित, मगर दंगाइयों के आका परेशान

लखनऊ, एजेंसी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2047 तक के लिए जो लक्ष्य तय किए हैं, उसके लिए देश के हर वक्ति, उद्योगी, कारोबार, हस्तशिल्पी, नौजवानों को अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से विवेदन करना होगा। राष्ट्र के प्रति हमारा समर्पण भाव, वर्तमान के साथ भावी पेंडिंगों के भवित्व को उज्ज्वल बनाने में योगदान देगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व एवं प्रधानमंत्री में भारत आज दुनिया की तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हुआ है। भारतीय अर्थव्यवस्था 10वें स्थान से



जाति के आधार पर बांधे लाली राजनीति से नहीं होगा: योगी

05वें स्थान पर पहुंच गयी है। हमें अगले 03 वर्षों में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। अर्थात् भारत को ग्लोबल के मैटरेंस के द्वारा भारत को विवेदन करना चाहिए। यहां पर स्वच्छता ही सेवा पर्याप्ति के अंतर्गत स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का अवधारणा विवरण यथा यथा। शिव प्रसाद गुरु मल्लिय विविक्षण बनवायेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्तदान शिविर का फर्स्ट की ■ शेष पेज 03 पर

सम्पादकीय

देश की बुनियाद पर प्रहार

महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलते हुए अदिंदा

की नीति को अपनाना, नेहरूजी की गुटनियेक्ष नीति और सविधान में कार्यपालिका, न्यायपालिका और पिधायिका इन तीनों के बीच स्पष्ट कार्य विभाजन और एक-दूसरे की सीमाओं का सम्मान, ये कुछ ऐसी विशिष्ट बातें हैं, जिनके कारण भारत के लोकतंत्र की दुनिया में अलग पहचान बनी। आजादी के 75 साल बाद भी भारत का लोकतंत्र मजबूत बना हुआ है और इस पर हो रहे तमाम प्रहार विफल हुए हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि भारत को बनाने वालों ने दूसरों के साथ जो विचार भारत की जड़ों में योग्य थे वो अब मजबूती से लोकतंत्र की दशा कर रहे हैं। लेकिन नोजूदा केंद्र सरकार भारत की इस द्वारित को चोट पहुंचाने में लगी है। बीते दिनों ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के घट गणपति पूजा में पहुंचे। विधायिका और कार्यपालिका से न्यायपालिका की एक सम्मानजनक दृष्टि होना चाहिए, लेकिन यहां वो दृष्टि निटी दिखी। श्री मोदी के शायनकाल में देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश उंजन गोगोई को दृज्यतामा का सदर्य बनाया गया, पूर्व राष्ट्रपति को एक देश, एक युनाव समिति का मुख्यिया बनाया गया। अब मुख्य न्यायाधीश के घट की निजी पूजा में प्रधानमंत्री के पहुंचने से कई किलो के सवाल रखे हुए, लेकिन भाजपा को इसमें कुछ गलत नजाए नहीं आ रहा।

माजणा को शायद इस बात में भी कोई आपत्ति नहीं है कि देश के याद्वीप गुरुत्व सलाहकार अग्नित डोमेल रस्ते के याद्वप्ति के सामने बैठकर उन्हें श्री जोदी के धूक्रेन दौरे की जानकारी दे रहे हैं। अब तक देश के प्रधानमंत्री विदेश दौरे से लौटते हुए ही प्रेस को अपनी यात्रा के बारे में बताते थे, ताकि उनके जरिए देशवासियों को पता चले कि हमारे प्रधानमंत्री ने किस देश में जाकर, क्या काम किया, जो हमारे लिए लाभकारी है। इसके बाद देश लौटने पर प्रधानमंत्री याद्वप्ति को अपनी यात्रा का ब्लौय देते थे लेकिन दूसरे देश के याद्वप्ति को इस तरह जानकारी देने का अर्थ क्या यह है कि भारत ने अपनी गुटनियेश नीति और स्वतंत्र विदेश नीति को छोड़ दिया है। क्या अब भारत की संप्रभुता को इस तरह दांव पर लगाया जाएगा। श्री जोदी को अब यह भी ख्याल कर देना चाहिए कि धूक्रेन जाने से पहले क्या उन्होंने सभी याद्वप्ति पुतिन की अनुमति भी ली थी। अगर धूक्रेन जाने का फैसला श्री जोदी ने संगम् याद् का गुरिया होने के नाते लिया था, तो अब कौन सी नज़रवृत्ति में उन्हें एनएसए को रस्ते बोजकर सफाई देनी पड़ी प्रधानमंत्री नरेन्द्र जोदी को यह भी बताना चाहिए कि विदेश मामलों में या दूसरे देशों पर कार्टवाई का फैसला अब उनके विदेश मंत्री, दक्षा मंत्री, केबिनेट इन सबकी सलाह से हो रहा है या भाजणा का कोई भी नोता इसके लिए बधान नहीं है।

दन का आधिकृत ह। पर्याप्त प्रयुक्ति ने उत्पादन का नुस्खानंत्री आदित्यनाथ योगी ने कहा है कि केवल 'जुट्टी' से काम नहीं चलेगा, बल्कि सुरक्षा के लिए 'सुरक्षन' भी आवश्यक है। इस बात का ध्यान एवं यहां नहीं देना है। बांगलादेश जैसे दियति की पुनर्जागृति यहां न होने पाए, इसके लिए ऐसी शक्तियों को हमें समाप्त करना है। हमें देश और धर्म को सुरक्षित रखना है। पाकिस्तान को मानवता का केंद्र और दुनिया का नायक बताते हुए श्री योगी ने कहा जब तक पाकिस्तान का अपेक्षण नहीं होगा, तब तक इलाज संभव नहीं है। पाकिस्तान का उपचार शुरू हो युका है। अब पाक अधिकृत कश्मीर के लोग भारत ने शानिल होना चाहते हैं। बलूचिस्तान भी पाकिस्तान से अलग होना चाहता है।



केरीवाल का दांव

कहने की जरूरत नहीं है कि आम तौर पर आम चुनाव के और खासतौर दिल्ली की सात सीटों पर चुनाव के नतीजों से, आम आदमी पार्टी ने निश्चित रूप से सबक लिया होगा। उसने खासतौर पर इस तथ्य से सबक तो जरूर लिया होगा कि इन सीटों पर भाजपा के मत फीसद में पिछले

आम चुनाव का
तुलना में कमी के
बावजूद और कांग्रेस
तथा आप पार्टी के
बीच पूर्ण चुनावी
समझौता होने और
अरविंद केजरीवाल के
विशेष जमानत पर
प्रचार के लिए
छूटकर, चुनाव प्रचार
करने के बावजूद,
भाजपा सभी
सात सीटों पर जीत
दर्ज कराने में
कामयाब रही।

- ललित गर्ग -

नरेन्द्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने के मौके पर भारतीय जनता पार्टी ने एक देश एक चुनाव के अपने चुनौतीपूर्ण संकल्प को लागू करने की बात कहकर राजनीतिक चर्चा को गरमा दिया है। भारत के लोकतंत्र की मजबूरी एवं चुनावी प्रक्रिया को अधिक प्रासंगिक एवं कम खचीला बनाने के लिये एक देश एक चुनाव पर चर्चा होती रही है। इसको लेकर भाजपा जिस तरह बेझिझक होकर तेजी से आगे बढ़ रही है, उससे



सुप्राम कॉट से जमानत पर
रिहाई के बाद, आम आदमी पार्टी के
कार्यक्रमांकों से अपने पहले संबोधन में ही,
अरविंद केजरीवाल ने उन्हें झंझोड़कर रख
देने वाला एलान कर दिया। केजरीवाल ने
कहा कि वह दो दिन में मुख्यमंत्री का पद
छोड़ देंगे। और उसके बाद मुख्यमंत्री का पद
तभी स्वीकार करेंगे, जब जनता उनके
ईमानदार होने पर अपने अनुमोदन की मोहर
लगा देगी। सुप्राम कॉट ने तो जमानत देकर
उनके ईमानदार होने पर कानूनी मोहर लगा दी
है, लेकिन उन्हें लगता है कि इतना काफी
नहीं है। अब वह जनता के सामने
अग्निरोक्षा देंगे और मुख्यमंत्री पद तभी
स्वीकार करेंगे, जब जनता उनके ईमानदार
होने पर अपने वोट से मोहर लगाएंगी। और
अपनी इस त्याग मुद्रा का दायरा बढ़ाकर, इसे
आम आदमी पार्टी की ही त्याग की मुद्रा
बनाते हुए, केजरीवाल ने अपने इस्तीफे के
फैसले के एलान में एक पेच और डाल दिया।
उन्होंने एलान किया कि उन्हीं की तरह,
व्यापक रूप से सरकार में नंबर-2 माने जाने
वाले, उप-मुख्यमंत्री तथा शिक्षा मंत्री, मनीष

एक देश एक
अंदाजा लगाया जा रहा कि केंद्र को सहयोगी दलों का पूरा समर्थन मिल रहा। दो बड़े दलों में से एक जेडीयू ने मोदी के एक देश एक चुनाव वाले इरादे पर सहमति जता दी है। कहा गया कि राजग सरकार अपने वर्तमान कार्यकाल के भीतर इस महत्वपूर्ण चुनाव सुधार को लागू कराने को लेकर आशावादी है और उसके इस आशावाद में देश को एक नई दिशा मिल सकेगी। भारत की वर्तमान चुनावी प्रणाली में निहित कई चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक राष्ट्र, एक चुनाव की अवधारणा एक संभावित समाधान के रूप

प्रसादों द्वाया भा इस अग्नपराक्षा का चुनाता स्वीकार करेंगे और जनता के ईमानदार घोषित करने के बाद ही, उप-मुख्यमंत्री तथा शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी संभवित हो। पुनः इसी प्रसंग को और आगे बढ़ाते हुए, एक और पेच जोड़िते हुए केजरीवाल ने यह मांग भी पेश कर दी कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव, जो अगली फरवरी में होने हैं, आगे खिसका कर नवबंबर में होने वाले महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के साथ करा दिए जाएं, ताकि केजरीवाल की अग्निपराक्षा जल्दी हो जाए। कहने की जरूरत नहीं है कि दिल्ली की मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा, केजरीवाल की इस गुगली से हटप्रभर रह गयी है। भाजपा के नेता, जो अब तक जेल में रहने के आधार पर केजरीवाल का इस्तीफा मांगते आ रहे थे, अचानक उनके इस्तीफे का एलान करने से समझ नहीं पा रहे हैं कि इसे अपनी कामयाबी मानें या अपनी परेशानी। यह कहने के सिवा कि केजरीवाल ने पहले ही इस्तीफा कर्मों नहीं दिया, वे ज्यादा कुछ कह नहीं पा रहे हैं। हाँ! आखिरकार काफी कसरत के बाद उहोंने यह नयी मांग जरूर निकाली है कि

चुनाव अमृतव में उभरी है। शासन के सभी स्तरों- पंचायत, नगरपालिका, राज्य और राष्ट्रीय-में एक साथ चुनाव कराने से लागत (खर्च)-प्रभावशीलता और प्रशासनिक दक्षता से लेकर बेहतर शासन और नीति निरंतरता तक कई लाभ मिल सकते हैं। यह नये भारत, सशक्त भारत एवं विकसित भारत के संकल्प को आकार देने का मुख्य आधार बन सकता है एवं आजादी के अमृतकाल की एक अमृत उपलब्धि बनकर सामने आ सकता है। भले ही स्पष्ट बहुमत के अभाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजग की तीसरी पारी में

एक देश एक चुनाव अमृतकाल की अमृत उपलब्धि बने

नरेन्द्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने के मौके पर भारतीय जनता पार्टी ने एक देश एक चुनाव के अपने चुनौतीपूर्ण संकल्प को लागू करने की बात कहकर राजनीतिक चर्चा को गरमा दिया है। भारत के लोकतंत्र की मजबूती एवं चुनावी प्रक्रिया को अधिक प्रासंगिक एवं कम खचीला बनाने के लिये एक देश एक चुनाव पर चर्चा होती रही है। इसको लेकर भाजपा जिस तरह बेझिझक होकर तेजी से आगे बढ़ रही है, उससे

म उभरा ह। शासन के सभा स्तरापंचायत, नगरपालिका, राज्य और राष्ट्रीय-में एक साथ चुनाव कराने से लागत (खर्च)-प्रभावशीलता और प्रशासनिक दक्षता से लेकर बेहतर शासन और नीति निरंतरता तक कई लाभ मिल सकते हैं। यह नये भारत, सशक्त भारत एवं विकसित भारत के संकल्प को आकार देने का मुख्य आधार बन सकता है एवं आजादी के अमृतकाल की एक अमृत उपलब्धि बनकर सामने आ सकता है।
भले ही स्पष्ट बहुमत के अभाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजग की तीसरी पारी में

केजरीवाल और सिसोदिया ही नहीं, पूर्व मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना चाहिए! बहरहाल, मुख्य विपक्षी पार्टी की प्रतिक्रियाओं से समझना मुश्किल नहीं है कि वह समझ ही नहीं पा रही है कि इस नवी स्थिति से कैसे निपटा जाए। जाहिर है कि चुनाव जल्दी कराने की आम आदमी पार्टी की मांग ने भाजपा को और भी चक्कर में डाल दिया है उसकी चुनाव जल्दी कराने में शायद ही कोई दिलचस्पी होगी, लेकिन चुनाव जल्दी कराए जाने का विरोध वह पार्टी है।

केसे कर सकता है, जो इसके दावे करता नहीं थकती है कि दिल्ली की जनता केजरीवाल की पार्टी से विश्वास उठ चुका है। बहराहाल, चुनाव जल्दी कराने के मुद्दे पर भाजपा, अपने हितों की रक्षा के लिए चुनाव आयोग पर भरोसा कर सकती है, जो वैसे भी केजरीवाल मनमुताबिक फैसला क्यों लेना चाहेगा? भाजपा के लिए इस मामले पर चुप लगाना ही काफी होगा। वैसे केजरीवाल ने भी विधानसभा भंग करने की सिफारिश नहीं करने और मन्त्रिमंडल से जल्दी चुनाव कराए जाने का प्रस्ताव पारित नहीं कराने के जरिए, इसका इशारा कर दिया है कि वह भी जल्दी चुनाव की आम मांग को प्रचार के स्तर पर ही रखने जा रहे हैं, उससे आगे नहीं बढ़ाने जा

रह हैं। अग्रिमपरीक्षा के जरिए अपना "सत" साबित करने का केजरीवाल का फैसला, एक राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक साबित होता है या नहीं, इसका फैसला तो सबसे बढ़कर दिल्ली के चुनाव में होगा। लेकिन, केजरीवाल की युगली ने भाजपा के लिए उसके खिलाफ अपने प्रचार की बैटिंग में रन बनाना, बहुत मुश्किल बना दिया है। दिल्ली शराब घोटाले के पूरे केस में कोई सचाई होने वा नहीं होने से अलग, इससे इंकार करना मुश्किल है कि इस केस में एक के बाद एक, आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी तथा लबे अर्से तक उन्हें जेल में बंद रखे जाने का, आम तौर पर इस पार्टी की छवि पर और खासतौर पर उसकी भ्रष्टाचार-विरोधी योद्धा की छवि पर, कुछ न कुछ असर जरूर पड़ा है। याद रहे कि यही छवि, मध्यवर्ग के बीच आप पार्टी के समर्थन का मुख्य आधार है। इसके साथ, दस साल से अधिक के शासन से पैदा हुई लोगों की निराशाएं जुड़कर, आप पार्टी के चेहरे पर बदहवासी की न सही, निचिंता की रेखाएं लाती ही थीं। केजरीवाल ने इस दांव से एक ही झटके में, इसी गिरावट को थामने की कोशिश की है कि कहने की जरूरत

बदलावकारी फैसले लेना उतना सहज नहीं रह गया है, जितना पहली-दूसरी पारी में नजर आता था। लेकिन भाजपा की सरकार इतनी भी कमजोर नहीं है कि अपने चुनावी वायदों एवं विकासमूलक कार्ययोजनाओं को लागू न कर सके। नरेन्द्र मोदी जैसा साहसी एवं करिशमाई नेतृत्व है तो उसके द्वारा देशहित की योजनाओं में आने वाले अवरोध वह दूर कर ही ले गें। एक दशक की विकासमूलक कार्यशैली के बाद अब भी भाजपा अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर अपनी योजनाओं को अंजाम तक पहुँचाने में जुटी है। भले ही

नहीं है कि आम तौर पर आम चुनाव के और खासतौर दिल्ली की सात सीटों पर चुनाव के नतीजों से, आम आदमी पार्टी ने निश्चित रूप से सबक लिया होगा। उसने खासतौर पर इस तथ्य से सबक तो जरूर लिया होगा कि इन सीटों पर भाजपा के मत फीसद में पिछले आम चुनाव की तुलना में कमी के बावजूद और कांग्रेस तथा आप पार्टी के बीच पूर्ण चुनावी समझौता होने और अरविंद केजरीवाल के विशेष जमानत पर प्रचार के लिए छूटकर, चुनाव प्रचार करने के

बावजूद, भाजपा सभी सात स्टारों पर जात दर्ज करने में कामयाब रही। इससे सफ था कि केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा आप सरकार के रास्ते में बाधाएं खड़ी किए जाने से लेकर, आप नेताओं के साथ उसके अत्याचार तक की सारी शिकायतें भी, दिल्ली के मतदाताओं को पर्याप्त रूप से प्रभावित नहीं कर पा रही थीं। इस अपर्याप्तता ने ही केजरीवाल को इस्तीफे की गुगली फेंकने के लिए प्रेरित किया लगता है, ताकि केंद्र में सत्ता में बैठी भाजपा के खिलाफ अपनी आलोचनाओं को और तीखी धार दे सके। केजरीवाल की इस्तीफे की गुगली के पीछे एक और भी कारण है। दिल्ली में, जहां उप-राज्यपाल के जरिए, केंद्र सरकार ने निर्वाचित सरकार के हाथ-पांव पहले ही बहुत ज्यादा बांध लिए हैं, केजरीवाल की जमानत पर रिहाई के साथ लगायी गयी राज्य सचिवालय नहीं जाने से लेकर किसी फाइल पर दस्तखत नहीं करने तक की शर्तें, व्यवहार में उनके लिए मुख्यमंत्री के रूप में काम करना ही बहुत कठिन बना देती थीं। ऐसे में चुनाव से चंद महीने पहले, लगातार उप-राज्यपाल से खींचतान में फंसी सरकार चलाने में उलझे रहने के मुकाबले में, केजरीवाल को यही ज्यादा फायदे का सौदा लगा होगा कि मुख्यमंत्री के पद पर अपने किसी ऐसे उत्तराधिकारी को बैठा दिया जाए, जिसके काम करने पर उतने बंधन नहीं होंगे और इसलिए चुनाव से पहले, दिल्लीवासियों के लिए हित के कुछ काम हो रहे होंगे। और खुद वह स्वतंत्रता के साथ जनता के बीच जाकर, भाजपा के विरुद्ध अभियान चलाने की स्थिति में होंगे।

फिर भी, केजरीवाल के लिए यह गुगली फेकना भी कोई आसान नहीं था। सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी जिस तरह की चंद नेताओं पर ही केंद्रित पार्टी है, जिसके केंद्र में केजरीवाल हैं और जिसका वैचारिक आधार ज्यादा मजबूत नहीं है, संघ-भाजपा

झारखंड का उदाहरण सामने है। पहले गिरफतारी के जरिए, हेमंत सोरेन की सरकार को गिराने की कोशिश की गयी। जब यह कोशिश नाकाम रही और मुख्यमंत्री के पद पर हेमंत सोरेन वापस भी आ गए, तो उनकी जेलयात्रा के दौरान एकजीदार मुख्यमंत्री बनाए गए चंपंई सोरेन को भाजपा ने तोड़ लिया। उनके सहारे एक अलग आदिवासी पार्टी खड़ी करने की कोशिश भी जब सिरे नहीं चढ़ी तो, उन्हें भाजपा में शामिल कर लिया गया। और अब खुद प्रधानमंत्री झारखंड में अपने चुनाव की घोषणा से पहले के चुनाव प्रचार में, भाजपा में नये-नये भर्ती किए गए चंपंई सोरेन तथा सीता सोरेन के नाम का, झारखंड मुक्ति मोर्चा पर हमले के लिए इस्तेमाल करते देखे जा सकते हैं। अब जबकि केजरीवाल, जनमत की अग्निपरीक्षा में खरा उत्तरने के बाद, फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के हिसाब से चल रहे हैं, वह निश्चय ही झारखंड के घटनाक्रम की दिल्ली में पुनरावृत्ति नहीं चाहेंगे। अस्थायी उत्तराधिकारी के पद पर भी वह ऐसे उम्मीदवार को लाना चाहेंगे, जो निजी तौर पर उनके प्रति वफादार भी हो और ज्यादा स्वतंत्र होने की कोशिश भी नहीं करे।

बेशक, केजरीवाल की गुगली का जहां तक अगले महीने के शुरू में हरियाणा में होने जा रहे चुनाव पर असर पड़ेगा, भाजपा को इसका परोक्ष लाभ भी मिल सकता है। याद रहे कि भाजपा, कांग्रेस के नेतृत्व में ईंडिया गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ने की संभावनाओं को पीठ दिखाकर, अब राज्य की सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बहरहाल, अरविंद केजरीवाल के अब खुद जोरदार तरीके से चुनाव प्रचार में जुटने का रास्ता खुल जाने के बावजूद, हरियाणा के चुनाव में आप पार्टी के बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरने तो दूर, कोई खास असर डालने में समर्थ होने की भी संभावनाएं कम ही हैं।

उपलब्धि बने

भाजपा-सरकार कई मुद्दों पर यू टर्न लेते हुए भी नजर आई। बहरहाल, लोकसभा में पहले के मुकाबले कमजोर स्थिति होने के बावजूद खुद को साहसिक निर्णय लेने वाली पार्टी के रूप में एक बार फिर अपने एक मुख्य एजेंडे एक राष्ट्र, एक चुनाव को आकार देने के लिये तत्पर हो गयी है। इसके लिए सरकार ने पक्ष-विपक्ष के सभी नेताओं से एक साथ आने का अनुरोध किया था। निस्सदैह, एक राष्ट्र, एक चुनाव के लिये भाजपा द्वारा नई पहल किए जाने के निहितार्थ राजनीति से ज्यादा राष्ट्रहित में है निश्चय ही हाएक देश एक चुनावहँ की योजना को लागू करना राजग के लिये बड़ी चुनौती होगी क्योंकि इस बार विपक्ष पहले के मुकाबले मजबूत भी है और एकजुट भी है। इसमें दो राय नहीं कि यह बात तार्किक है कि एक राष्ट्र, एक चुनाव का प्रयास शासन में सुनिश्चितता लाएगा। वहीं बार-बार के चुनाव खचीर्ते होते हैं। दूसरे राज्य-दर-राज्य लंबी आचार संहिता लागू होने से विकास कार्य भी बाधित होते हैं। साथ ही साथ शासन-प्रशासन व सुरक्षा बलों की ऊर्जा के क्षय के अलावा जनशक्ति का अनावश्यक व्यय होता है।

यूक्रेन संघर्षः कारगर नहीं हुआ भारत का शाति प्रयास

जैसे-जैसे रूस यूक्रेन के डोनेट्स्क क्षेत्र में पूर्वी शहर पोक्रोव्स्क पर कब्जा करने के करीब पहुंच रहा है, कुर्स्क में यूक्रेन द्वारा हासिल बढ़त का असर कम हो रहा है। रूस, यूक्रेन के दोनेट्स्क क्षेत्र में पूर्वी शहर पोक्रोव्स्क पर कब्जा करने के करीब पहुंचते हुए कुर्स्क में यूक्रेन द्वारा हासिल की गई बढ़त को चुनौती दे रहा है। वहां कुस्त सैनिकों ने कई रूसी गांवों पर कब्जा कर लिया है। स्थिति में लगातार बदलाव होते रहे हैं। रूस ने अभी एक रणनीतिक स्थान मेमरिक गांव पर कब्जा करने की घोषणा की है जो कीव के रसद केंद्र पोक्रोव्स्क की ओर जाता है और लगभग 20 किमी दूर है। यूक्रेनी सरकार ने पहले ही पोक्रोव्स्क में स्थानीय आबादी को इलाका खाली करने के आदेश दे दिए हैं जो बता रहे हैं कि दो युद्धरत देशों के बीच शांति लगातार घट हो रही है। यह भी लागता है कि शांति स्थापना के नई दिल्ली के प्रयास काम नहीं आए हैं। हालांकि पीएम मोदी की हालिया यूक्रेन यात्रा के दौरान शांति प्रयासों से बहुत उम्मीद न की गई थी। युद्ध एक महत्वपूर्ण दौर में पहुंच गया है और दोनों पक्षों की ओर से राहत वे कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। अगर पीएम की यह यात्रा उनकी पिछली मॉस्को यात्रा पर नाराजगी को शांत करने के लिए थी तो प्रधानमंत्री के मध्यस्थिता के इशारे ने गुस्से को शांत करने कोशिश को कम नहीं किया बल्कि उनके यूक्रेनी मेजबान ने अपनी बाद की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान इस संघर्ष के बारे में भारत के विट्कोण में कई विसंगतियों की ओर इशारा करते हुए जो कहा है वह उनकी नाराजगी को बताता है। जुलाई में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक के तुरंत बाद पोलैंड (21-22 अगस्त) और यूक्रेन (23 अगस्त) (यूक्रेन के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर) की पीएम मोदी की योजनाबद्ध यात्रा, रूस और यूक्रेन के बीच 30 महीने के संघर्ष में मध्यस्थिता का भारत का सीधा प्रयास प्रतीत होता है। भारत ने शांति के लिए एकमात्र मार्ग के रूप में 'बातचीत और कूटनीति' का आङ्गान करने में एक सुसंगत रुख अपनाया है और दोनों पक्षों के हितों को ध्यान में रखते हुए बातचीत के द्विपक्षीय समाधान के प्रयास किए और दोनों राष्ट्रपतियों जेलेंस्की और पुतिन दोनों के साथ बैठकें कीं। इस सिलसिले में आखिरी बार क्रमशः जून में इटली में जी-7 बैठक और इस साल जुलाई में मास्को में द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के मौके पर बातचीत हुई थी। शिखर बैठक के

दैरान राष्ट्रपति पुतिन को गले लगाने वाले प्रधानमंत्री मोदी के चित्र जब छप रहे थे उसी वक्त रूसी मिसाइलों ने यूक्रेन में बच्चों के अस्पताल पर हमला किया था जिसमें कैंसर से पीड़ित बच्चे मारे गए थे जिसकी वजह से यूक्रेन के राष्ट्रपति नाराज थे। इस हमले ने पश्चिमी देशों को और नाराज कर दिया तथा नाटो की 75 वीं वर्षगांठ के लिए समय में वार्षिंगटन डीसी में उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया।

उस पृष्ठभूमि के खिलाफ और दोनों बड़े शक्ति गठबंधनों के बीच अपने संतुलन कार्य को जारी रखते हुए, भारत के प्रयासों को यूक्रेनी पक्ष पर चिंताओं को दूर करने और पश्चिम के संघर्ष में जाहिर भारतीय नीति के साथ सहज महसूस करने के लिए सोचा जा सकता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसने पश्चिम खुश नहीं है क्योंकि भारत ने रूस को हमलावर के रूप में घोषित करने से परहेज किया है एवं संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ कई प्रस्तावों से परहेज किया है। इसके अलावा जी-7 की बैठक के तुरंत बाद 24 जून की स्विट्जरलैंड में यूक्रेन द्वारा आयोजित शांति सम्मेलन में भारत की ओर से जूनियर स्तर का प्रतिनिधि मंडल भेजा गया और बैठक की संयुक्त घोषणा पर भारत की ओर से हस्ताक्षर भी नहीं किए गए। इस सम्मेलन में 80 से अधिक देशों ने भाग लिया था। एक निष्पक्ष शांतिदूत के रूप में भारत की स्थिति को इस संघर्ष के संदर्भ में अच्छा नहीं माना

राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूरोपीय राजधानियों और अमेरिका की अपनी लगातार यात्राओं में (वार्षिंगटन डीसी में कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करने के साथ) अपनी 10-सूत्री शांति योजना के लिए समर्थन और लड़ाई जारी रखने के लिए हृथियारों की लगातार आपूर्ति की पैरवी की है जिसका बाइडेन प्रशासन ने पूरा समर्थन किया है।

